

अमेरिका में जनभावना इज़रायल-ईरान युद्ध में अमेरिका के सीधे हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ

इकॉनमिस्ट/यू गव के सर्वेक्षण के अनुसार, 60 प्रतिशत जनता अमेरिकी सेना के सीधे हस्तक्षेप के खिलाफ है, केवल 16 प्रतिशत जनता अमेरिका के हस्तक्षेप के पक्ष में है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 जून। इजरायल और ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर तक बढ़ता जा रहा है। इधर अमेरिका में इकोनॉमिस्ट/यूगव के एक नए सर्वेक्षण में अमेरिकी जनता की स्पष्ट राय नज़र आई है, 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इजरायल-ईरान संघर्ष में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का विरोध किया है। इसके विपरीत, केवल 16 प्रतिशत लोग अमेरिकी हस्तक्षेप के पक्ष में हैं। यह परिणाम अमेरिकी जनता में युद्ध को लेकर बढ़ती उदासीनता को दर्शाता है, जो पिछले दो दशकों में मध्य पूर्व में खबौंते सैन्य अभियानों और इस समय घरेलू राजनीति में चल रही उथल-पुथल से उपजी है।

यह भावना कोई क्षणिक मनोदशा नहीं, बल्कि अमेरिकी जनमत में लंबे

- **इराक व अफगानिस्तान में अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद वर्षों युद्ध चला, इन युद्धों से परेशान अमेरिकावासी, अब किसी दूसरे देश में जाकर अमेरिका लड़े, इस बात से तंग आ गए हैं।**
- **विशेषकर “मिडिल ईस्ट” में वे अमेरिकी सेना का सीधा हस्तक्षेप नहीं चाहते, क्योंकि यह भावना घर कर गई है कि जब भी अमेरिका हस्तक्षेप करता है, युद्ध और लम्बा हो जाता है तथा नतीजा पूर्णतया अमेरिका के पक्ष में हो, ऐसा नहीं होता।**
- **अमेरिका की जनता, विशेषकर, ईरान के विरुद्ध युद्ध में उतरने के खिलाफ है। क्योंकि ईरान की ओर से “प्रॉक्सी वॉर” लड़ने के लिए कई जगह के लोग तैयार हैं, जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में, इराक के शिया समर्थक तथा यमन के हाउथी। अतः संभावना यह बनती है कि युद्ध शीघ्र व्यापक रूप धारण कर लेगा, जैसा वियतनाम में हुआ था, जहाँ अमेरिका लम्बे व अनिर्णित युद्ध में फंस गया था।**
- **अमेरिका की युवा पीढ़ी में यह भावना जोरों से उभरी है कि कूटनीति व युद्ध को रोकना और भड़कने न देना, बेहतर नीति है।**

समय से चल रहे बदलाव का हिस्सा है।

इराक और अफगानिस्तान में वर्षों तक

चले युद्ध के बाद, सभी अमेरिकन चाहे

वे किसी भी राजनैतिक रूझान के हों,

दूसरे देशों में सैन्य हस्तक्षेप को लेकर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुलिस बदले की भावना से पकड़ेगी तो हम पुरजोर विरोध करेंगे : सचिन पायलट

शनिवार सुबह राजस्थान युनिवर्सिटी में परीक्षा दे रहे छात्रनेता निर्मल चौधरी और विधायक अभिमन्यु पूनिया को पुलिस ने हिरासत में लिया

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने शनिवार को पत्रकारों से रूबरू होकर राजस्थान युनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी और संगरिया (हनुमानगढ़) के विधायक अभिमन्यु पूनिया को पुलिस द्वारा हिरासत में लिये जाने की निंदा की। पायलट ने कहा कि “पुलिस, प्रशासन और सरकार अगर बदले की भावना से किसी को पकड़ती है तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगर सरकार यह बात रखना चाहती है कि, जो लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सरकार का इस्तेमाल करके अगर किसी की बात को दबाना चाहते हैं, तो इसको मैं गलत मानता हूँ।”

- **पुलिस का कहना है कि “निर्मल चौधरी के साथ विधायक अभिमन्यु पूनिया जबरदस्ती गाड़ी में घुसे थे, उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया था।”**
- **शनिवार सुबह दोनों नेताओं को पकड़ने के लिए युनिवर्सिटी कैम्पस में पुलिस सादा वर्दी में पहुंची थी। पुलिस ने उन्हें परीक्षा कक्ष से निकालकर पुलिस वैन में बैठाया था।**

पायलट ने कहा कि, हर जनप्रतिनिधि कोई आंदोलन करता है, धरना देता है, तो उसको अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को संविधान यह छूट देता है कि अपनी बात को रखे। मुझे लगता नहीं कि, किसी ने जान-बूझकर कानून की कोई अवहेलना की होगी।

गौरतलब है कि शनिवार सुबह

राजस्थान युनिवर्सिटी से छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरी और संगरिया (हनुमानगढ़) के विधायक अभिमन्यु पूनिया को पुलिस ने हिरासत में लिया था। दोनों शनिवार सुबह युनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र की परीक्षा देने आए थे, तभी पुलिस ने पकड़ लिया। कैम्पस में सुबह से ही सिविल ड्रेस में पुलिस ने डेरा डाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में पहली बार योग हुआ

जगदलपुर, 21 जून। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर के अतिसंवेदशील इलाके के पहाड़ी में जवान और ग्रामीण मिलकर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में दहशत को पीछे छोड़ते हुए खुले मन से शनिवार को पहली बार भाग लिए।

एक सौ पचासवीं बटालियन के कमांडेंट राकेश शुक्ला ने बताया कि सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों

- **आदिवासियों व सुरक्षाबलों के जवानों ने साथ मिलकर योग किया।**

पूर्वति, सिलगेर और टेकलगुडैम स्थित सीआरपीएफ के कैपों में जवानों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। ग्रामीणों ने पहली बार बिंदगी में जाना कि योग क्या है और जवानों के संग मिलकर योग किया। जवानों ने ग्रामीणों को बताया कि योग स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए वरदान है। योग के बाद ग्रामीणों में खशी का माहौल था।

चुनाव आयोग ने मतदान की वैबकास्टिंग सार्वजनिक करने से इन्कार किया

नयी दिल्ली, 21 जून। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों की वेब-कास्टिंग के रिकार्ड को किसी व्यक्ति या राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराये जाने की मांग को मतदाताओं की निजता की दृष्टि से एक जोखिम भरा मुद्दा बताया है और कहा है कि इसका उपयोग असामाजिक तत्वों द्वारा मतदाताओं पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है।

आयोग के सूत्रों ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मतदान की वेबकास्टिंग की नयी

- **चुनाव आयोग ने कहा, इससे मतदाताओं की निजता को खतरा हो सकता है।**

व्यवस्था आंतरिक उपयोग के लिए की है। इसका उद्देश्य मतदान केंद्र की गतिविधियों के प्रबंध को सुचारु रखना है। वेबकास्टिंग के रिकार्ड को किसी चुनाव आयोग के संदर्भ में उच्च न्यायालय के निर्देश पर तो न्यायालय के विचारधीन प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन उसे किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को देना स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की भावना के विरुद्ध होगा।

आयोग के एक सूत्र ने कहा,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या वाकई में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पहली बार भारत की विदेश नीति लड़खड़ा रही है?

कांग्रेस के शासन में पले-बढ़े भारत के पुराने कूटनीतिज्ञ, इसी सोच में रंगे हुए हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 21 जून। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत की विदेश नीति एक नाजुक एवं संकटपूर्ण मोड़ पर खड़ी नज़र आ रही है, जिससे वरिष्ठ राजनयिकों और वैश्विक मामलों के विशेषज्ञों में चिंता की लहर दौड़ गई है। ईरान-इजरायल संकट के तेजी से बिगड़ते हालात को संभालने में रणनीतिक समझ और स्पष्टता की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की आलोचना बढ़ती जा रही है।

एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त राजनयिक ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर सरकार की विदेश नीति की कड़ी आलोचना करते हुए, एक प्रमुख भू-राजनीतिक चुनौती के सामने, दिशाहीन होने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “नई दिल्ली ने अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता की

‘ईरान, भारत का पुराना आजमाया हुआ मित्र है’

सोनिया गांधी का मानना है कि कई बार यू.एन. में भारत के खिलाफ मानवाधिकार हनन के बारे में आलोचनात्मक प्रस्ताव लाने का प्रयास हुआ है, ईरान ने ये प्रस्ताव “ड्रॉप” करवाये हैं

- **सोनिया गांधी की सोच है कि अब गाज़ा में भारी बमबारी व जान-माल का भारी नुकसान हुआ है तथा ईरान पर भी मिसाइल व प्लेन्स व ड्रोन्स का हमला कूटनीति के स्थापित तौर तरीकों के पूर्णतया खिलाफ है।**
- **अतः भारत को इस मौके पर चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि मुखरित होकर अपनी बात कहनी चाहिए।**

स्थिरता की पूरी तरह अनदेखी करते हुए किया गया। ऐसी कार्रवाइयों केवल अस्थिरता बढ़ाएंगी और आगे के संघर्ष की ज़मीन तैयार करेंगी।

उन्होंने कहा कि यह हमला उस समय हुआ जब ईरान और अमेरिका के बीच के कूटनीतिक प्रयास सकारात्मक संकेत दे रहे थे, जो इसे और भी अधिक पीड़ादायक बनाता है। इस वर्ष अब तक पाँच दौर की वार्ताएँ हो चुकी थीं, और जून में छठा दौर प्रस्तावित था। मार्च 2025 में, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने कांग्रेस में स्पष्ट रूप से कहा था कि ईरान परमाणु हथियार कार्यक्रम नहीं चला रहा है, और उसके सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने 2003 में परमाणु कार्यक्रम का निलंबन कर दिया था। उसके बाद से इसे फिर शुरू करने की अनुमति नहीं दी है।

सोनिया गांधी ने कहा कि यह याद रखना जरूरी है कि वर्तमान इजरायली नेतृत्व, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, शांति को कमजोर करने और कट्टरवाद को बढ़ावा देने का एक लंबा और दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है। उनकी सरकार का लगातार अवैध बस्तियों का विस्तार, अतिराष्ट्रवादी गुटों के साथ गठबंधन करना और दो-राष्ट्र समाधान में बाधा डालना न केवल फिलिस्तीनी जनता की पीड़ा को बढ़ाता है, बल्कि पूरे क्षेत्र को लगातार संघर्ष की ओर धकेलता है।

इतिहास हमें याद दिलाता है कि नेतन्याहू ने 1995 में नफरत की आग इतनी बढ़ाई की उसकी वजह से इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन की हत्या कर दी गई, जिससे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **इन लोगों का मानना है कि भारत ने अपनी पुरानी विदेश नीति, जो सामरिक दृष्टि से स्वतंत्र सोच पर आधारित थी, त्याग दी है।**
- **भारत की यह विदेश नीति, रिएक्टिव, “शॉर्ट साइटेट” दृष्टिकोण पर आधारित है तथा अमेरिका से प्रभावित है। इस परिवर्तन से भारत को खास लाभ नहीं हुआ, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इसने भारत की विश्वसनीयता को ठेस पहुँचायी है।**
- **इन पुराने कूटनीतिज्ञों का यह भी कहना है कि वॉशिंगटन व तेल अवीव के नज़दीक जाकर, उनका पक्ष लेकर भारत ने “मिडिल ईस्ट” में अपने पुराने साथियों, मित्रों का विश्वास खोया है।**
- **विदेश नीति के इन जानकारों का इस लय में यह भी मानना है कि भारत पहले अपने सिद्धांतों पर आधारित दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था तथा शांति और कूटनीति के पक्ष में बोलता था, बिना किसी के दबाव में आकर।**
- **ये विशेषज्ञ पुरानी विदेश नीति का गुणगान तो करते हैं, पर, यह भूल जाते हैं कि भारत एक “मेजर प्लेयर” है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अपनी आर्थिक सफलता व सफल कूटनीति के कारण।**

परंपरा को त्याग दिया है और अमेरिका केन्द्रित तात्कालिक सोच वाली नीति को

अपनाया है।” उनके अनुसार, इस बदलाव से भारत को कोई ठोस लाभ

नहीं मिला है, बल्कि इससे उसकी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ग्राम विकास अधिकारी से रिकवरी पर रोक लगाई

जयपुर, 21 जून। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने करौली की मंडरायल पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ निकाली गई 3.70 लाख रुपए की रिकवरी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख पंचायती राज सचिव और स्थानीय जिला परिषद के मुख्य

- **सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने पंचायतीराज के प्रमुख सचिव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जवाब मांगा।**

कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य से जवाब तलब किया है। अधिकरण के अध्यक्ष विकास सीताराम भाले और सदस्य लेखराज तोषावड़ा ने यह आदेश बनवारी लाल की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि विकास कार्यों में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)